दैनिक जागरण

गलती स्वीकार करना उसे सुधारने की दिशा में पहला कदम होता है

पाकिस्तान का रोना-धोना

जम्मू-कश्मीर पर रूस के बयान के बाद यह और अच्छे से स्पष्ट हो गया कि इस मसले पर पाकिस्तान को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। रूस ने जम्मू-कश्मीर संबंधी अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले को भारत का आंतरिक मामला करार दिया है। कुछ ऐसी ही राय अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात व्यक्त कर चुका है। चीन ने अवश्य लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर असहमति जाहिर की है, लेकिन इसके आसार कम हैं कि वह जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान के सुर में बोलेगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि हांगकांग पर उसे भी विश्व समुदाय से नरम रवैये की दरकार है। पाकिस्तान यह जो उम्मीद लगाए है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मामले में कुछ करेगी उसके पूरे होने की संभावना नगण्य है। बीते सात दशकों में जम्मू-कश्मीर संबंधी सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुरूप कुछ नहीं हो सका तो पाकिस्तान के कारण ही। जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह के लिए उसे सबसे पहले अपने कब्जे वाले इलाके से अपनी सेनाओं को हटाना था। उसने यह काम किया नहीं और फिर भी यह शोर मचाता रहा कि भारत आगे नहीं बढ़ रहा है। उसकी चीख-पुकार सुरक्षा परिषद की ओर से सुने जाने की गुंजाइश इसलिए भी नहीं, क्योंकि वह खुद कश्मीर के एक हिस्से गिलगित-बाल्टिस्तान की स्थिति में परिवर्तन कर चुका है। आखिर वह किस अधिकार से यह अपेक्षा कर रहा है कि सुरक्षा परिषद उसका रोना-धोना सुनने के लिए तैयार होगी?

पाकिस्तान को इसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि यह वही था जिसने शिमला समझौते को कभी महत्व नहीं दिया। सबसे खराब बात यह रही कि वह अपनी जनता को यह झूठा सपना दिखाता रहा कि कश्मीर उसका हिस्सा बनकर रहेगा। इस सपने को टूटना ही था, क्योंकि यह दिवास्वप्न था। पाकिस्तान के हित में यही है कि वह कश्मीर को भूलकर आगे बढ़े। उसने कश्मीर पर अपना बेजा अधिकार जताकर अपने को तबाही की ओर ले जाने का ही काम किया है। आज अगर पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ बन गया है तो कश्मीर को येन-केन-प्रकारेण हासिल करने की जिद के कारण ही। पता नहीं वह यह साधारण सी बात समझने को तैयार क्यों नहीं है कि कश्मीर का मतलब केवल घाटी ही नहीं है। जम्मू भी उसका हिस्सा है और कल तक लद्दाख भी था। इन क्षेत्रों की जनता कभी भी उस रुख-रवैये से सहमत नहीं हुई जो घाटी के कुछ लोग व्यक्त करते रहे। अगर पाकिस्तान यह समझ रहा है कि भारत से राजनयिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध तोड़कर अथवा दुनिया भर में शोर मचाकर भारत पर दबाव डालने में समर्थ हो जाएगा तो यह ख्याली पुलाव ही है।

पुजारियों के लिए भत्ता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर भाजपा मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। इस आरोप ने उस समय और जोर पकड़ लिया था, जब इमामों व मोअज्जिमों को भत्ता देने का एलान किया गया था। जब इमामों व मोअज्जिमों को भत्ता देना शुरू किया गया, तब हिंदू पुजारियों ने भी भत्ते की मांग शुरू कर दी थी। बाद में हाईकोर्ट में जब मामला पहुंचा तो इमामों व मोअज्जिमों को भत्ता देने पर रोक लगा दी गई, लेकिन दूसरे रास्ते से भत्ता जारी रखने का ममता सरकार पर आरोप लगा। इस बीच जब हिंदू संगठन भाजपा को बंगाल में प्रभाव बढ़ाने में मदद करने लगे तो तृणमूल को भी बात समझ में आने लगी, हालांकि पुजारियों को भत्ता नहीं मिला। अब ममता कैबिनेट के मंत्री राजीव बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार हिंदू पुजारियों के लिए मासिक भत्ते की लंबे समय से लंबित मांग पर 'गौर' करेगी। भाजपा यह आरोप लगाती रही है कि राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसी आरोप से पीछा छुड़ाने के लिए अब इस समुदाय तक पहुंचने के प्रयास के तहत मंत्री ने कहा कि हिंदू पुजारियों का बहुत बड़ा समुदाय है। वे लंबे समय से वंचित हैं। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि मासिक भत्ते की उनकी मांग पर गौर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सनातन ब्राह्मण सम्मेलन के इतर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा-'हमें लगता है कि उन्हें मासिक भत्ता मिलना चाहिए क्योंकि सैकड़ों पुजारी हैं, जिन्हें अपने परिवार को चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।' तृणमूल पर लगते तुष्टीकरण के आरोपों के बीच ऐसे में यह बयान अहम है। पुजारियों के संगठन के अध्यक्ष श्रीधर शास्त्रीने कहा-'ब्राह्मण राज्य में वंचित व उपेक्षित हैं। हमारा कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए। जो भी हमारी मांगे पूरी करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे।' लगभग 1.83 लाख पुजारी शास्त्री के संगठन के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि 35,000 गरीब पुजारियों की एक सूची जारी की गई है, जिन्हें 2,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाना चाहिए। भत्ते पर तृणमूल के वादे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष दिलीप घोष ने पूछा कि ममता सरकार को हिंदू पुजारियों के कष्ट दिखने में इतना समय क्यों लग गया?'

एक ऐतिहासिक फैसला

संजय गुप्त

कांग्रेस और उसके सुर में सुर मिला रहे दल कुछ भी कहें, वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि दुनिया निर्णायक फैसले लेने वाले नेताओं को ही सलाम करती है

अवधेश राजपूत

मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर संबंधी अनुच्छेद 370 और 35-ए को हटाने की जो पहल की उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह की छवि मजबूत और निर्णायक कदम उठाने वाले नेता के तौर पर उभरी है। यह अफसोस की बात है कि कांग्रेस समेत कुछ अन्य दल यह समझने से इन्कार कर रहे हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किसी निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि देश के भले के लिए लिया गया। इसे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान अच्छे से स्पष्ट भी किया। उन्होंने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यह भरोसा दिलाया कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन वहां के हालात बदलने के लिए किया गया। उन्होंने न केवल यह आश्वासन दिया कि जम्मू-कश्मीर को कुछ कालखंड के लिए केंद्र के अधीन रखा गया है, बल्कि असहमत लोगों की आपत्तियों का आदर करने के साथ उनके सवालों का समाधान करने की भी बात कही। इसके साथ ही उन्होंने इस अनुच्छेद से मुक्ति को एक सच्चाई बताते हुए यह कहने में भी संकोच नहीं किया उसकी वजह से अलगाव, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और भेदभाव को बढ़ावा मिला। यह एक सच्चाई है। यह अनुच्छेद अलगाववाद को बढ़ाने के साथ कश्मीरी जनता के तुष्टीकरण का भी जरिया बन गया था।

कांग्रेस और कुछ अन्य दल कुछ भी कहें, अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला देश हित में था। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि उसे हटाने के प्रस्ताव और जम्मू-कश्मीर को नए सिरे से गठित करने संबंधी विधेयक राज्यसभा में भी आसानी से पारित हुए और लोकसभा से भी। ऐसा इसीलिए हुआ, क्योंकि कई विपक्षी दलों ने भी सरकार का साथ दिया। इनमें से कुछ विपक्षी दल वे भी हैं जो इस पर आपत्ति जताया करते थे कि भाजपा अपने चुनावी घोषणा पत्रों में अनुच्छेद 370 हटाने का वायदा करती रहती है। भाजपा ने अपने इस ध्येय को कभी छिपाया नहीं कि समय आने पर वह इस अनुच्छेद को हटाएगी, जबकि आजादी के बाद उसे तैयार करने का काम एक तरह से गुपचुप तरीके से ही किया गया था। अनुच्छेद 370 शेख अब्दुल्ला और नेहरू की देन था। शेख अब्दुल्ला की कश्मीर का शासक बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ही नेहरू ने कश्मीर के प्रधानमंत्री रह चुके गोपालस्वामी आयंगर के जरिये अनुच्छेद 370 तैयार कराया था। इस अनुच्छेद के मसौदे से तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल भी असहमत थे और कांग्रेस के साथ-साथ संविधान सभी के ज्यादातर सदस्य भी। नेहरू के जोर देने पर इसे न चाहते हुए भी संविधान में जोड़ा गया। इसके नतीजे अच्छे नहीं रहे। जिन शेख अब्दुल्ला के प्रभाव में आकर नेहरू ने अनुच्छेद 370 संविधान में जुड़वाया उन्हें एक समय देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार तक करना पड़ा, फिर भी नेहरू को अपनी गलती का अहसास नहीं हुआ। उस समय के अनेक नेताओं को इस गलती का अहसास हो गया था। इसी कारण इस अनुच्छेद का विरोध शुरू हो गया था। नेहरू और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच हुए एक समझौते के विरोध में सरकार से इस्तीफा देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना कर कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे का विरोध शुरू कर दिया। इस विरोध के दौरान ही जेल में उनकी मृत्यु हो गई। जनसंघ बाद में भाजपा में तब्दील हो गई, लेकिन उसने अपना यह संकल्प कभी नहीं छोड़ा कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाएगा।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर का सही मायनों में भारत के साथ एकीकरण हुआ है। इस अनुच्छेद को हटाकर सरकार ने उस गलती को ठीक करने का काम किया जो नेहरू ने की थी। कांग्रेस चाहती तो समय रहते इस गलती को ठीक कर सकती थी। अतीत में जब अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को निष्प्रभावी किया गया तब कांग्रेस उसे पूरी तरह समाप्त कर सकती थी, लेकिन शायद उसने इसलिए ऐसा नहीं किया ताकि यह संदेश न जाए कि नेहरू ने एक बड़ी गलती कर दी थी। संभवतः इसी कारण कांग्रेस अनुच्छेद 370 को हटाने की निंदा करना पसंद कर रही है। अपने नेताओं के बयानों से हो रही किरकिरी के बाद भी कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार इस रवैये पर अड़ा है कि अनुच्छेद 370 हटाना सही नहीं। यह रवैया तब है जब कांग्रेस के कई नेता मोदी सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। इनमें जनार्दन द्विवेदी से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और महाराजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह भी शामिल हैं। लगता है कि गांधी परिवार अभी भी इससे चिंतित है कि नेहरू पर किसी तरह का आक्षेप न लगने पाए। आखिर उसे देश के हितों की चिंता है या नेहरू के नाम की? सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस के समय अनुच्छेद 370 पर संसद में सही तरह से बहस भी क्यों नहीं हो सकी, जबकि अतीत में न जाने कितनी बार कश्मीर हिंसा और कर्फ्यू से ग्रस्त रहा।

राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह सही सवाल उठाया कि आखिर यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की गई कि इस अनुच्छेद से जम्मू-कश्मीर अथवा देश को हासिल क्या हुआ? कांग्रेस और साथ ही अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध करने वाले अन्य विपक्षी दल यह सवाल तो कर रहे हैं कि कश्मीर के लोगों को भरोसे में नहीं लिया गया, लेकिन वे इसकी अनदेखी कर रहे हैं कि इस अनुच्छेद को तैयार करते समय भी लोगों को भरोसे में नहीं लिया गया था। आखिर गलती को बनाए रखना सही है या फिर उसे ठीक करना? क्या यह महज दुर्योग है कि आज गांधी परिवार और अब्दुल्ला परिवार एक जैसी बातें कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने यह रेखांकित करके सही किया कि अनुच्छेद 370 की आड़ में पाकिस्तान को कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद भड़काने का मौका मिला। इस अनुच्छेद को हटाने से वह इसीलिए बौखलाया हुआ है, क्योंकि यह धारणा ध्वस्त हो रही है कि कश्मीर विवादास्पद क्षेत्र है और पाकिस्तान को वहां किसी तरह का दखल देने का अधिकार है। इस पर आश्चर्य नहीं कि विश्व समुदाय उसकी नहीं सुन रहा है। इसमें एक योगदान मोदी सरकार की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का भी है। कांग्रेस और उसके सुर में सुर मिला रहे दल कुछ भी कहें, वे इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि दुनिया निर्णायक फैसले लेने वाले नेताओं को ही सलाम करती है। मोदी और शाह ने कश्मीर पर जो निर्णायक फैसला लिया उस पर अंतरराष्ट्रीय जनमत भारत के अनुकूल ही है।

कश्मीर को शांत-संतुष्ट करने के लिए वहां विकास और रोजगार के वे विशेष उपाय करने ही होंगे जिनका उल्लेख प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया। राज्य में जैसे-जैसे निवेश बढ़ेगा और उद्योग-व्यापार फले-फूलेगा वैसे-वैसे वहां के लोगों को इसका अहसास होगा कि अनुच्छेद 370 उनके विकास में बाधक बना हुआ था। यह भाव ही माहौल शांत करने का काम करेगा। वहां ऐसा माहौल बने, इसकी चिंता सारे देश को करनी चाहिए।

response@jagran.com

विचारधारा की तलाश

हास्य-व्यंग्य

-आप क्या करते हैं जनाब ?

-जी, एक लेखक हूं!

-कौन सी पार्टी के लेखक हैं?

-यह क्या कह रहे हैं आप...! लेखक भी कभी किसी पार्टी का लेखक होता है क्या?

-क्यों नहीं हो सकता...जब एक लेखक की अपनी खुद की पार्टी हो सकती है। तब किसी पार्टी का लेखक होना कौन-सी आश्चर्य की बात है?

-खुद की पार्टी मतलब?

-मतलब, बहुतेरे लेखक भी किसी न किसी लेखक-गुट से जुड़े ही होते हैं..और क्या!

-आप हम लेखकों का मान गिरा रहे हैं? क्या लेखक के लिए किसी पार्टी से वाबस्ता होना जरूरी होता है?

-एकदम जरूरी होता है, श्रीमान?

-यह आप कैसे कह सकते हैं?

-अरे, जनाब अब आप ही देख लीजिए...कोई लेखक वामपंथी करार दे दिया गया है...तो कोई दक्षिणपंथी...! कोई अगड़ापंथी है...तो कोई पिछड़ापंथी! कोई दलित लेखक है..तो कोई सवर्ण! कोई इस गुट से है..तो कोई उस गुट से! मतलब, बेपंथ का तो कोई भी लेखक ही नहीं है?

-होते होंगे कोई लेखक ये पंथी और वो पंथी! मगर हम तो गुटनिरपेक्ष पंथ के लेखक हैं!

-यह पंथ-निरपेक्ष लेखन तो सुना था, मगर यह निरपेक्ष-पंथ लेखन क्या बला है जी?

-जी हम किसी लेखक-गुट या सियासी-पार्टी के लिए नहीं लिखते! बल्कि हम तो बस अपने दिल की आवाज पर कलम चलाते हैं!

राजेश सेन

जब एक लेखक की अपनी खुद की पार्टी हो सकती है। तब किसी पार्टी का लेखक होना कौन-सी आश्चर्य की बात है?

-खैर ये सब छोडिए और सच-सच बताइए...आप किस विचारधारा से जुड़े लेखक हैं ?

-लेखक की भी कोई विचारधारा होती है क्या ?

-होती क्यों नहीं है..?

-मगर हम तो इतना जानते हैं...विसंगति, बुराई, अत्याचार के खिलाफ सामाजिक चेतना और जन-जागृति ही लेखक की वास्तविक विचारधारा होती है...?

-यह तो एक आदर्शवादी बात हो गई.! बगैर विचारधारा के किसी कलम की सहज यात्रा अच्छी नहीं मानी जाती है।

यह अजीब धारणा कैसे बना रखी है जनाब?

-हाल में किसी लेखक को बगैर किसी विचारधारा का पिछलग्गू समझने का चलन ही जाता रहा है! कोई इस पाले में है...तो कोई उस पाले में! और जो किसी पाले में नहीं है...वह पाले की रस्सी थामे बैठा है...!

-लगता है आप आधुनिक लेखकों के चरित्र-सार को लेकर घोर पूर्वाग्रही हैं।

-क्या करें साहब...आप जैसा निष्पाप सोचने को दिल ही नहीं करता..!

-तो इसके लिए लेखकों को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?

-ठहराना पड़ता है साहब...! विचाराधारा के बगैर समकालीन लेखकों को निर्दोष देखने-समझने का दस्तूर जो नहीं है..!

-अच्छा तो आप ये बताइए कि ये विचारधारा क्या बला होती है..?

-वही जो ब-रस्ते सियासत और सत्ता के हमें पढाई और समझाई जाती है!

-तब क्या सियासत की भी अपनी कोई विचारधारा होती है ?

-होती ही होगी...तभी तो वे विभिन्न विचारधाराओं के पैरोकार माने जाते हैं!

-तब बताइए...सत्ता किसकी विचारधारा होती है ?

-वह भी सियासत का ही अपना दुरूह लक्ष्य होती है!

-तब यह भी बताइए कि..सियासत के लिए विचारधारा बड़ी होती है या फिर सत्ता!

-बेशक..सत्ता..!

-तब फिर किसी विचारधारा की किसी सत्ता के आगे क्या बिसात हुई?

-निश्चित ही वह सत्ता की बांदी हुई!

-बिल्कुल, सियासत के लिए सत्ता पथ पर विचारधारा की बिसात एक फोल्डिंग पलंग से ज्यादा कुछ नहीं है! जिस पर पल-दो-पल विश्राम कर चतुर सियासत अपने लक्षित गंतव्य की ओर आसानी से आगे बढ़ जाती है!

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य

संसद के हालिया सत्र में विभिन्न कार्यों में व्यतीत समय

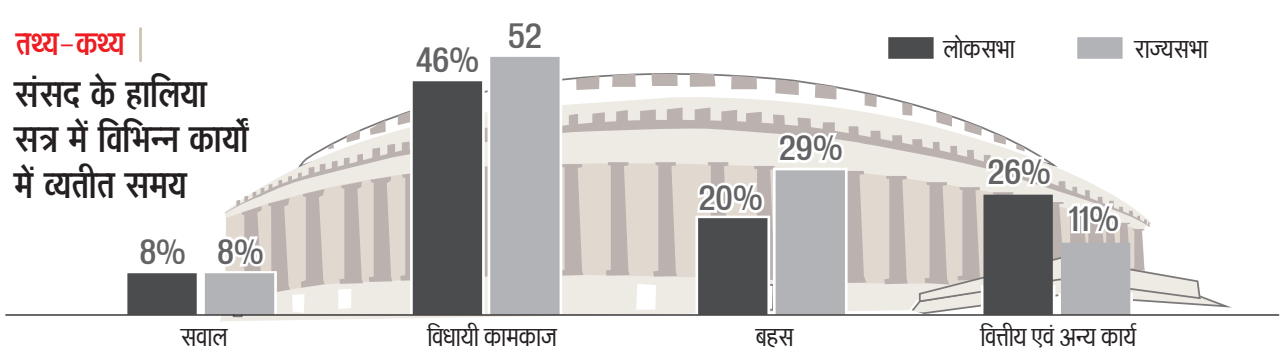

ऊर्जा

आभार का चमत्कार

जीवन में किसी उपकार के बदले कृतज्ञता व्यक्त करना एक प्रमुख मानवीय गुण है। यह विनम्रता का परिचायक माना जाता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने की आकांक्षा के लिए जरूरी है कि आप शुक्रिया कहना, धन्यवाद देना और आभार जताना सीखिए। इससे सफलता की राह और सरल बनाई जा सकती है। जो कृतज्ञता महसूस करते हैं, उनमें अपनत्व की संभावनाएं अधिक होती हैं। आभार एक ऐसी संवेदना है जो न केवल बेहतर जीवन की राह खोलती है, बल्कि हमें अपनी परेशानियों में भी सुकून महसूस कराती है। जो लोग आभार व्यक्त करना जानते हैं, वे जीवन जीने की कला में पारंगत हो जाते हैं।

उन्हें जिंदगी जीने की कला आती है। तकलीफों और परेशानियों को वे जीवन का हिस्सा मानते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा होता है कि वे अपनों की बदौलत उस मुश्किल वक्त को भी पार कर लेंगे। ऐसे भाव से आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपने भीतर परिवर्तन महसूस करेंगे। एक अध्ययन के अनुसार ऐसे लोग जो अपने जीवन में शुक्रिया शब्द का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं, वे जीवन में आने वाली कठिनाइयों के साथ बेहतर ढंग से तालमेल बिठा लेते हैं और कम दबाव में होते हैं। हृदय की सच्ची भावनाओं से प्रकट किया आभार बहुत कारगर होता है। यदि आप किसी बुरे समय से गुजर रहे हैं तो धन्यवाद का एक शब्द आपके दिमाग को ऊर्जा देगा, सोचने की शक्ति को बढ़ाएगा और आपको लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रदान करेगा। यदि आप हर दिन शुक्रिया के साथ शुरू करते हैं तो आपका सामाजिक दायरा बढ़ता है।

धन्यवाद और कृतज्ञता का नजरिया हमारी सोच और जीवन को विस्तृत बनाता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि यदि आपके पास परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार और घर है। आपको इन सबके लिए आभारी होना चाहिए। कृतज्ञ या आभारी होने की वजहें किसी अन्य लोक से नहीं आतीं, बल्कि हमारे निकट दैनंदिन जीवन का हर पल हमें कृतज्ञ होने का संदेश देता है।

ललित गर्ग

बोलकर काम करेगा लेजर हथियार

मुकुल व्यास

आपको यह जानकार कुछ अटपटा लग सकता है कि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन एक ऐसा लेजर हथियार विकसित कर रहा है जो मनुष्य की तरह आवाज उत्पन्न करता है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में इस अनोखे हथियार के परीक्षण का एक दौर पूरा भी कर लिया है। पेंटागन द्वारा विकसित की जा रही इस नई तकनीक से संवेदनशील जगहों से लोगों को दूर रखने के लिए उन पर फ्लैशलाइट फेंकने या लाउडस्पीकरों से संदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह नई तकनीक पेंटागन के 'नॉन-लीथल वीपंस डायरेक्टोरेट प्रोग्राम' का हिस्सा है जिसका उद्देश्य दुश्मनों को मारने के बजाय उन्हें दूसरे तरीकों से काबू करना है।

इस प्रोजेक्ट के तहत शोधकर्ता ऐसा लेजर विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जो बोलने के अलावा कम दूरियों पर कांच के आर-पार संक्षिप्त संदेश भी भेज सकती है। शोधकर्ताओं का यह भी दावा है कि 'बोलने वाला' लेजर हथियार लंबी दूरी तक भी मनुष्य की आवाज के स्पष्ट सुनाई देने वाले अंश संप्रेषित कर सकता है। इस काम को अंजाम देने के लिए

इसका मकसद विरोधी को मार गिराने के बजाय उन पर दूसरे तरीकों से काबू पाना है। एक परीक्षण पूरा भी हो चुका है

यह हथियार 'लेजर प्रेरित प्लाज्मा प्रभाव' का उपयोग करता है। इसके लिए शक्तिशाली लेजर किरणें दाग कर प्लाज्मा की गेंद उत्पन्न की जाती है और दूसरी लेजर दाग कर इस प्लाज्मा में कंपन पैदा किया जाता है। इससे ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। सही फ्रीक्वेंसी पर दागी गईं लेजर किरणों से प्लाज्मा में उत्पन्न होने वाले कंपन मनुष्य जैसी आवाज पैदा कर सकते हैं।

सुनने में यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन एक न्यूज वेबसाइट 'मिलिट्रीटाइम्स डॉट कॉम' की एक रिपोर्ट के अनुसार, सेना के इस्तेमाल के लिए ऐसा हथियार आगामी पांच वर्षों में उपलब्ध होने की भरपूर संभावना है। इसके द्वारा जारी किए गए वीडियो में इस हथियार का एक नमूना भी दिखाया गया है। वीडियो में इस हथियार को एक दीवार पर कई बार लेजर किरणें दागते हुए दिखाया गया है। इन किरणों से यह आवाज निकलती है कि 'रुक जाओ वरना हम आप पर गोली चलाने के लिए बाध्य होंगे।' भविष्य में सेना इस हथियार का उपयोग लोगों के किसी खास वर्ग को संदेश या चेतावनी देने के लिए कर सकती है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े मुख्य वैज्ञानिक डेव लॉ ने न्यूज वेबसाइट को बताया, 'उनका अगला कदम लेजर हथियार के परीक्षण की दूरी को 100 मीटर तक करना है जिसे धीरे-धीरे कई किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। हमारा लक्ष्य अंततः एक ऐसा लेजर हथियार विकसित करने का है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक स्पष्ट संदेश प्रेषित कर सके। इस तरह के हथियार से हवाई जहाज से भी संदेश जारी किए जा सकते हैं और लोगों को सैनिक प्रतिष्ठानों से दूर रहने के लिए चेताया जा सकता है।'

बोलने वाले लेजर मुख्य रूप से संचार का जरिया होंगे, लेकिन इसमें सुधार कर इसका उपयोग भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट से जुड़े पेंटागन के वैज्ञानिक एक ऐसे प्लाज्मा लेजर पर काम कर रहे हैं जो कपड़ों में सुराख करके त्वचा पर जलन या खुजली उत्पन्न कर सकती है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राजरंग

शाह की चर्चा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आजकल नेताओं के बीच चर्चा में हैं। भाजपा के विरोधी दलों के सांसदों की भी तमन्ना है कि उनकी पार्टी के नेता भी वैसे ही हों। दरअसल पिछले सत्र में दो बार, एक तो आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए एनआइए बिल में संशोधन और दूसरी बार कश्मीर से धारा 370 के हटाए जाने के वक्त शाह दोनों सदनों में लंबा बोले। बिंदुवार बोले और एक भी सवाल ऐसा नहीं रहा जिसे उन्होंने अनुत्तरित छोड़ा हो। लंबी बहस चली थी और इस दौरान गलियारे में कई सांसदों को आपस में शाह की प्रशंसा करते देखा गया। कुछ विपक्षी सांसद तो यह भी कहते सुने गए कि पार्टी का अध्यक्ष ऐसा ही होना चाहिए, काम तो लेते हैं, लेकिन जीत भी सुनिश्चित कराते हैं।

काम न आया स्टारडम

भाई-भतीजावाद और पैरोकारी के सहारे नकारा को भी नायक बनाने को लेकर राजनीति भले बदनाम हो, मगर इस संस्कृति से दूसरे क्षेत्र भी अछूते नहीं हैं। खासकर हिंदी सिनेमा जगत में तो अभिनेता-अभिनेत्री से लेकर गीतकार-संगीतकार और निर्देशन से लेकर निर्माण सभी में कुछ खास लोगों का सिक्का चलता है। बॉलीवुड में इन्हें अघोषित रूप से फिल्मी घराने का दर्जा हासिल है। जाहिर तौर पर ऐसे प्रभावशाली घराने अपने कैंप के नायक-नायिकाओं का हित देखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसी हित चिंता का ताजा उदाहरण अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के चयन के दौरान सामने आया। शुक्रवार को पुरस्कारों का एलान होने से एक दिन पहले मुख्य जूरी के एक सदस्य को बॉलीवुड के बड़े स्टार सलमान खान ने फोन किया। फिल्म 'जीरो' में अभिनेत्री कैटरीना कैफ के अभिनय की तारीफ करते हुए उन्हें पुरस्कारों की सूची में शामिल करने की गुंजाइश तलाशने का प्रयास किया। मगर उन्हें पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया पूरी हो जाने और किसी गुंजाइश का रास्ता नहीं होने का संदेश दे दिया गया।

तुगलकी सेवानिवृत्ति

रेलवे में आए दिन विचित्र कार्य होते रहते हैं जिनका कोई सिर-पैर नहीं होता। इसी तरह का एक वाकया पिछले दिनों ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष उन्नीकृष्णन के साथ हुआ जिन्हें 29 जुलाई को अचानक तुगलकी फरमान के तहत जबरन सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया। ऐसा 55 साल की उम्र या 30 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को रिटायर करने की नई नीति के कारण हुआ है, लेकिन इस मामले में खास बात ये है कि उन्नीकृष्णन को ऐसे वक्त पर जबरन सेवा से निष्कासित किया गया जबकि उन्होंने एक मई को स्वयं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर रखा था और 31 जुलाई को उन्हें स्वतः रिटायर हो जाना था। उनका सर्विस रिकॉर्ड भी बेदाग था, लेकिन गिनती पूरी करने के चक्कर में इस काम में लगे अधिकारियों ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। इससे भी आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इस कदम से रेलवे को उन्हें तीन माह का अतिरिक्त वेतन देना पड़ा, जो कि स्वतः रिटायर होने में नहीं देना पड़ता। गुरुवार को पूरे देश के स्टेशन मास्टरों ने काली पट्टी बांध कर उन्नीकृष्णन के साथ हुए इस सुलूक का विरोध किया।

दाखिले बंद हैं

गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल खुलने के बाद से ही बच्चों के एडमिशन की दिक्कत से ज्यादातर माता-पिता परेशान रहते हैं। खासतौर पर केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का एडमिशन कराने के आकांक्षी अभिभावकों की लाइन काफी लंबी होती है। सभी लोग इसकी सिफारिश के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में जुगाड़ की तलाश में रहते हैं। इसलिए इन दिनों मंत्रालय में ऐसे लोगों की आवाजाही जरूरत से ज्यादा रहती है। यह सिलसिला स्कूलों में दाखिला बंद होने तक चलता रहता है, लेकिन इस बार मंत्रालय ने ऐसी भीड़ के प्रवेश को रोकने के लिए नया तरीका अपनाया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर ही बड़े-बड़े शब्दों में 'केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन बंद हो गए' का नोटिस टांग दिया गया है।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।